कपड़ा मिलों का बन्द किया जाना

103. श्री मोहन स्वरूप :
श्री यशपाल सिंह :
श्री ना० रा० शर्मा :
श्री शारदा नन्द :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री राम सेवक यादव :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री सीताराम केसरी :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री शशि रंजन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन कपड़ा मिलों को स्थायी रूप से अपने हाथ में लेने का निर्णय कर लिया है जो उत्पादन की दृष्टि से बेकार सिद्ध हुए हैं अथवा जो आमतौर पर बंद रहती हैं;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय से कितनी मिलों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है ; और

(ग) इस निर्णय के कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) सरकार, कुछ कमजोर और बहुत कम लाभ वाली वस्त्र मिलों, जिन्हें आर्थिक दृष्टि से चलने योग्य समझा जाता है परन्तु जो कुछ कारणों से या तो बंद हो गई हैं या बंद होने ही वाली हैं, को अपने हाथ में लेने के प्रस्ताव पर सक्रियरूप से विचार कर रही है ।

(ख) और (ग). ऐसी मिलों की संख्या का ठीक ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता । यह विचार है कि सरकार के निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक विधान संसद् के चालू सत्र में पुरःस्थापित कर दिया जायेगा ।

Idle capacity in Public Undertakings

*104. **Shri Umanath:**
Shri K. Ramani:

Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to state:

(a) the extent of unutilised capacity in each of the public sector undertakings under his Ministry and the reasons therefor; and

(b) the steps Government propose to take to utilise the full capacity?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) By and large, the capacity in the public sector undertakings under the Ministry of Industrial Development and Company Affairs is still in the process of being installed and it would not be correct to attempt at this stage an expression in exact terms of the extent to which the capacity has remained unutilised. It is, however, realised that there is a gap in the utilisation of capacity already installed in some of the public sector undertakings. This is attributable to certain reasons of which the most important is the inadequacy of orders arising as a result of the temporary slowing down of development in sectors such as Railways, Steel mills, Power projects, construction industry, coal mining and the like.

(b) The Heads of the Public Undertakings have already been asked to work out schemes for achieving a fuller utilisation of capacity, *inter alia*, by—

(i) strengthening the sales organisation with a view to stepping

up exports as well as heightening domestic sales;

(ii) diversifying production for fabrication of items which have a market including the production of spares which have a repetitive demand;

(iii) forming consortia for taking up contracts on a turn-key basis. One such consortium would be formed as a standing arrangement for meeting the requirements of Steel, structural and Heavy Engineering industries and another for supplying the requirements of power projects. Similar consortia with private sector units wherever feasible would also be formed on an *ad-hoc* basis for taking up turn-key jobs as and when such occasions arise.

Diesel and Electric Trains during Fourth Plan

***106. Shri Swell:**
Shri Kikar Singh:
Shrimati Nirlep Kaur:
Shri Barrow:
Shri Kolai Birua:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under the consideration of Government to introduce more diesel and electric trains during the Fourth Plan;

(b) if so, the full details of the Scheme; and

(c) the places where the diesel and electric trains are proposed to be introduced?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) to (c). A statement giving the required information is laid on the Table of the Sabha. [Placed in *Library*. *See* No. LT-461/67].

आयात नीति

***107. श्री विभूति मिश्र :**
श्री क० ना० तिवारी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री रा० कृ० बिड़ला :
श्री राम किशन गुप्त :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा 1 मई, 1967 को घोषित नई आयात नीति की मुख्य बातें क्या हैं, और इसका कैसा प्रभाव होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : अप्रैल 67—मार्च 68 की अवधि के लिए 1 मई 67 को घोषित आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अंतर्गत आयात नीति की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(1) 59 प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के विषय में आयात लाइसेंस, छोटे और बड़े पैमाने के दोनों क्षेत्रों में, आवश्यकता पर आधारित होंगे और लगातार दिये जाते रहेंगे ।

(2) सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों को अब लाइसेंसों के लिए आवेदन करने से पहले अपने प्रशासकीय मंत्रालय से विदेशी मुद्रा सम्बन्धी अनुमति नहीं मांगनी पड़ेगी । इनके आवेदन पत्र तकनीकी विकास महानिदेशालय के जरिये भेजे जायेंगे ।

(3) कार्यविधी को सरल बनाने की की दृष्टि से कुछ आवश्यक मशीनों के फालतू पुर्जों, जिनके लिये अमेरिकी सहायता शर्तों के अधीन अमेरिका से आयात